खण्ड-9 संख्या-10

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान सभा (वादवृत्त)

भाग-2, कार्यवाही प्रश्नोत्तर-रहित

बृहस्पतिवार, तिथि 7 जुलाई, 1988 ई०

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है। आदिवासी, हरिजनों के नाम पर रोने वाली सरकार है और उन्हीं पर जुल्म हो रहा है और सरकार चुपचाप रहेगी। हम लोग सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, किस के लिये ? गरीबों के लिये, हरिजनों के लिये, आदिवासियों के लिये, गरीब जनता के लिये। आपसे यही आग्रह है कि इसके लिये आप सरकार को कहें।

अध्यक्ष : आपने कहा, सरकार ने उसे सुना। सरकार चर्चा के दौरान अपनी नीति स्पष्ट कर देगी। स्थान ग्रहण कीजिये।

(शोरगुल)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

अत्यधिक लोक महत्व के विषय पर सूचनाएं एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :

ध्यानाकर्षण

श्री रणजीत सिंह : जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चल रहे दुर्गावती डैम के 31 चेन से 51 चेन के कार्य में श्री एस.डी.एन. वर्मा, अधीक्षण अभियंता, श्री सी. दयालु, कार्यपालक अभियंता, श्री एम.एन. तिवारी, प्रबंध निदेशक, निर्माण निगम एवं संबंधित संवेदक की मिली भगत से करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। डैम का उक्त भाग का कार्य क्षेत्र डैम डिवीजन नं.। से कटवा कर नीतिगत परम्पराओं के विपरीत केनाल डिवीजन के अन्तर्गत लाया गया। स्वीकृत नक्शा नहीं प्राप्त रहने के बावजूद निविदा आमंत्रित करते हुए निर्माण निगम से सामंजस्य कर प्रबंध निविदा एवं मनोनयन के आधार पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से

एक ही संवेदक को मनचाहे दर पर पूरे कार्य आवंटित करवा कर सरकार को लगभग 1.50 करोड़ रुपये का नुकसान दिया गया है। इसके अतिरिक्त जमीन के ब्लाक लेवल में हेराफेरी 2 फीट स्ट्रीपिंग के बजाय 10 फीट स्ट्रीपिंग एवं स्ट्रीपिंग से निकली मिट्टी को मशीन द्वारा ढुलाई का भुगतान तथा बरसात के मौसम में बिना कप्पेंक्शन के डैम भराई जैसा घोर अनियमित कार्य करा कर लगभग एक करोड़ से भी अधिक रुपये का लूट किया गया है। अत: कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने, निविदा में जालसाजी कर ऊंची दर पर कार्य आवंटन कराने एवं कार्य में अनियमितता बरत कर करोड़ों रुपये का लूट की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात की ओर कि अभी आदिवासियों के क्षेत्रों में डेवेलपमेन्ट की बात उठी है, मेरे ख्याल से बिहार सरकार की नीति है आदिवासियों की उन्नति के लिये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिये काफी प्रयास किये हैं, इसके लिये फंड एलौट किया गया है और काम भी चल रहा है लेकिन इस तरह की बात, चाहे गलतफहमी में या जो भी सच्चाई हो या गलत हो, उसको सरकार को दूर कर देना चाहिए जब इस तरह की बात पर माननीय सदस्यगण उत्तेजित हो जायं। आदिवासियों के क्षेत्रों की बात उठायी गयी है, मैं समझता हूँ, कोई साधारण बात नहीं है जो शून्य काल में उठायी जाय तो उसे अनसुनी कर दें, इसका सरकार पर, सारे सदन पर असर पड़ता है और इसीलिये मेरे ख्याल से सरकार ने आदिवासियों, हरिजनों के लिये काफी योजनाएं बनायी है और आदिवासियों की उन्नति के लिये काफी प्रयास भी हो रहे हैं तो इसपर कम से कम शॉर्ट में इस

गलतफहमी को सरकार को दूर कर देना चाहिए।

श्री भागवत झा "आजाद" : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी आदेश दिया कि सामान्य प्रशासन के विवाद पर इसपर कहा जाय। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ शून्य-काल में जितने प्रश्न उठाये जाते हैं, आपने भी यह निदेश दिया है कि उस समय में, सामान्य प्रक्रिया में, हर बात का जवाब सरकार तुरत नहीं दे सकती है लेकिन जो बात रामलखन बाबू ने कहा, तो यह स्पष्ट है कि सरकार आदिवासियों के संबंध में, हरिजनों के संबंध में, निर्धनों के संबंध में बराबर प्रयत्नशील रही है और बराबर प्रयत्न कर रही है लेकिन उनके किस प्रश्न का जवाब दिया जाय। उन्होंने सारी बातें नकारात्मक बतायी, कुछ हुआ ही नहीं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, यह बात कही जा रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ नारों और भाषणों से और मैं अपने कार्यों से आदिवासियों के लिये भलाई का कार्य कर रहा हूँ। यह बात स्पष्ट है, आपका आदेश था, उसके अनुसार बाकी

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन में वापस आ गए)

सारी बातों पर बाद में सविस्तार से कहा जायगा, शून्य-काल में अचानक प्रश्न उठाये जाते हैं, और हर बात का जवाब, हमारा अंदाजा है, आपका निदेश है उस समय में नहीं दिया जा सकता, सरकार उपयुक्त समय पर ऐसी बातों का जवाब देती रही है और देती रहेगी।

श्री सत्यनारायण दुदानी : अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी परिपाटी रही है कि शून्य-काल में यदि कोई महत्वपूर्ण बात उठायी जाती है तो आप सरकार को निदेश देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसपर

सरकार को निदेश दीजिए।

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने नकारा नहीं है, उन्होंने कहा कि शून्य-काल में बहुत सारी बातें आती हैं, सरकार तुरन्त उसपर बयान या रिएक्ट नहीं कर सकती है और इसलिये मैंने जब यह कह दिया कि सामान्य प्रशासन पर वाद-विवाद के समय, इस मामले को स्पष्ट रूप से रखा जायगा तो मैं सोचता हूँ कि इसमें और बात नहीं होनी चाहिए।

श्री सत्यनारायण दुदानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि श्री राम नारायण राम जी के प्रश्न पर विचार करुंगा, मैं आपके कक्ष में मिला भी था। श्री राम नारायण राम जी के प्रश्न.....

अध्यक्ष : उनका क्या प्रश्न था ?

श्री सत्यनारायण दुदानी : श्री डी.एन.राम के विषय पर था।

अध्यक्ष : जब वह आयेगा तब न ?

श्री सत्यनारायण दुदानी : मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें इनका भी नाम जोड़ दिया जाय ताकि उनको भी कहने का मौका मिल सके।

अध्यक्ष : मैं उनको मौका दूंगा।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य

(क) दुर्गावती डैम के निर्माण में बरती गई अनियमित्ता की जांच

श्री लहटन चौधरी : वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, डिहरी के आदेश से डैम के उक्त भाग का कार्य क्षेत्र (31 चेन से 51 चेन) डैम प्रमंडल संख्या I से काट कर नहर प्रमंडल के अधीन कार्यहित में लाया गया। डैम प्रमण्डल